केंद्रीय बजट 2026-27 : प्रमुख तथ्य एवं विश्लेषण

1. विषय (Theme)

दृष्टि (Vision) : विकसित भारत (Viksit Bharat)
युवा शक्ति (Yuva Shakti) के माध्यम से

तीन स्तम्भ (Three Pillars)

1. **सतत आर्थिक वृद्धि** (उत्पादकता, लचीलापन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता)
2. **आकांक्षाओं की पूर्ति** (क्षमता निर्माण और युवा सशक्तिकरण)
3. **सबका साथ, सबका विकास** (समावेशी एवं संतुलित विकास, अंतिम व्यक्ति तक लाभ)

मार्गदर्शी सिद्धांत (Guiding Principles)

• दुविधा पर नहीं, कर्म पर ज़ोर	• बयानबाज़ी पर नहीं, सुधार पर ज़ोर	• लोकलुभावनवाद पर नहीं, जनहित पर ज़ोर

2. व्यापक आर्थिक परिदृश्य (Macroeconomic Outlook)

सूचकांक	वित्त वर्ष 2026-27 (बजट अनुमान)
नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि	10%
वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि	~7%
राजकोषीय घाटा	4.3% सकल घरेलू उत्पाद का
ऋण-से-जीडीपी अनुपात	55.6%
पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)	₹12.21 लाख करोड़
प्रभावी पूंजीगत व्यय (Effective Capex)	₹17.1 लाख करोड़ (4.4% GDP)

- कुल व्यय (Total Expenditure) : ₹53.47 लाख करोड़
- राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) : ₹41.25 लाख करोड़
- शुद्ध कर प्राप्तियां (Net Tax Receipts) : ₹28.67 लाख करोड़
- विनिवेश लक्ष्य (Disinvestment Target) : ₹80,000 करोड़

3. स्तम्भ I – सतत आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बनाए रखना

(A) अग्रिम विनिर्माण (Frontier Manufacturing)

① बायोफार्मा शक्ति (Biopharma SHAKTI)
- कुल प्रावधान ₹10,000 करोड़ (5 वर्ष)
- फोकस – बायोलॉजिक और बायोसेमिलर
- 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPERs)
- 7 मौजूदा NIPERs का उन्नयन
- केंद्रीय औषधि मानक निचंत्रण संगठन (CDSCO) का आधुनिकीकरण

② भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (ISM 2.0)
- उपकरण निर्माण, कच्चे माल का विकास
- अनुसंधान एवं विकास (R&D)
- उद्योग-नेतृत्व वाले कौशल विकास केंद्र

③ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक योजना
- योजना का विस्तार
- बजटीय प्रावधान बढ़कर ₹22,919 करोड़ से ₹40,000 करोड़

④ महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा तत्व
- स्थायी मैग्नेट निर्माण हेतु दुर्लभ मृदा कॉरिडोर की स्थापना – उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में
- प्रोसेसिंग मशीनरी पर सीमा शुल्क में छूट

⑤ रासायनिक पार्क
- 3 प्लग-एंड-प्ले रासायनिक पार्क

(B) एमएसएमई को बढ़ावा (MSME Push)
- SME ग्रोथ फंड – ₹10,000 करोड़
- सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड – ₹2,000 करोड़
- 200 पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों का उन्नयन (अधोसंरचना और प्रौद्योगिकी)
- कॉर्पोरेट मित्र (Corporate Mitras) – छोटी इकाइयों को वैश्विक वैल्यू चेन्स से जोड़ने हेतु मेंटरशिप नेटवर्क

(C) अवसंरचना और कनेक्टिविटी (Infrastructure & Connectivity)

रेल (Rail)
- 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर :
  - मुंबई-पुणे
  - पुणे-हैदराबाद
  - हैदराबाद-बेंगलुरु
  - हैदराबाद-चेन्नई
  - चेन्नई-बेंगलुरु
  - दिल्ली-वाराणसी
  - वाराणसी-सिलिगुड़ी

लॉजिस्टिक्स (Logistics)
- डंकूनी-सुरत समर्पित माल गलियारा (DFC)
- 20 राष्ट्रीय जलमार्ग का परिचालन
- तटीय माल प्रोत्साहन योजना (Coastal Cargo Promotion Scheme)

शहरी विकास (Urban Development)
- सिटी इकोनॉमिक रीजन (CERs)
- प्रत्येक क्षेत्र के लिए ₹5,000 करोड़ (5 वर्ष की अवधि में, चैलेंज मोड में)

जोखिम वित (Risk Financing)
- अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड की स्थापना – निर्माण चरण में आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करेगा

4. स्तम्भ II – आकांक्षाओं की पूर्ति

① रचनात्मक एवं 'ऑरेंज' अर्थव्यवस्था
- एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) कंटेंट क्रिएटर लैब
- 15,000 विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में

② महिला एवं STEM समावेशन
- प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास (Girls' Hostel) की स्थापना हेतु पूंजीगत सहायता

③ पर्यटन और आतिथ्य
- एकीकृत आयुष एवं डायग्नोस्टिक सेवाओं सहित 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब (Regional Medical Hubs)
- राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (NCHMCT) को उन्नत कर राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान बनाया जाएगा

④ खेल विकास
- व्यापक 'खेलो इंडिया मिशन' का शुभारंभ
- खेल सामान निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल

5. स्तम्भ III – सबका साथ, सबका विकास (समावेशी एवं संतुलित विकास)

1) कृषि – भारत-VISTAAR
- बहुभाषी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सलाहकार प्लेटफॉर्म
- एग्री-स्टैक (AgriStack) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के डाटा का एकीकरण
- किसानों को फसल, मिट्टी, मौसम, बाजार और कीट प्रबंधन पर व्यक्तिगत सलाह

2) महिला सशक्तिकरण
- SHE Marts (Self-Help Entrepreneur Marts) की शुरुआत
- स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को मार्केट एक्सेस
- लखपती दीदी नेटवर्क का विस्तार

(5) विदेशी क्लाउड डेटा सेंटर
- भारतीय डेटा सेंटर के माध्यम से विदेशी ग्राहकों को सेवाएँ देने वाले विदेशन सांस्थानों को 2047 तक कर छूट

3) स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य
- NIMHANS-2 की स्थापना
- रांची और तेजपुर स्थित संस्थानों को क्षेत्रीय Apex संस्थान (Regional Apex Institutions) के रूप में उन्नत किया जाएगा
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान की क्षमता में वृद्धि

4) क्षेत्रीय विकास एवं पूर्वोदय पर विशेष ध्यान
- उत्तर-पूर्व में बौद्ध पर्यटन परिपथ (Buddhist Tourism Circuit) का विकास
- पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पूर्वी तटीय औद्योगिक गलियारा (Industrial Corridor) का नोड
- पूर्व क्षेत्र के लिए 4,000 इलेक्ट्रिक बसों का आवंटन – स्वच्छ एवं हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा

6. कर सुधार और विधायी परिवर्तन

(A) प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes)

1) नया आयकर अधिनियम, 2025
- 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी
- आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा
- कर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं

2) शेयर बायबैक पर कराधान
- कर का भार कंपनी से हटाकर शेयरधारक पर
- बायबैक से प्राप्त राशि को पूंजीगत लाभ (Capital Gains) माना जाएगा

3) प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) में वृद्धि
- फ्यूचर्स : 0.02% → 0.05%
- ऑप्शंस : 0.10% → 0.15%

4) गिफ्ट सिटी (IFSC)
- ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों (OBU) हेतु कर छूट अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष
- इसके बाद 15% कर

(B) परोक्ष कर (Indirect Taxes & Customs)

1) स्रोत पर कर संग्रह (TCS) को तर्कसंगत बनाया गया
- LRS (विदेश शिक्षा/चिकित्सा) और विदेश यात्रा पैकेज पर TCS दर घटाकर समतल 2%

2) व्यक्तिगत आयात शुल्क (Personal Import Duty)
- सामान्य व्यक्तिगत आयात शुल्क 20% से घटाकर 10%

3) शुल्क में छूट
- 17 कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों के उपचार पर पूर्ण छूट

4) निर्यात प्रोत्साहन
- समुद्री (Marine), चमड़ा (Leather) और कपड़ा (Textile) क्षेत्रों के लिए ड्यूटी-मुक्त इनपुट आयात सीमा में वृद्धि

7. समग्र विश्लेषण (Analytical Assessment)

सकारात्मक पक्ष (Positives)
- ✓ अब तक का सर्वाधिक सार्वजनिक पूंजीगत व्यय – विकास को गति
- ✓ राजकोषीय अनुशासन जारी – घाटा निचंत्रण में
- ✓ सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भविष्य के उद्योगों को बल
- ✓ एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक एकीकरण में सुधार
- ✓ अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स तथा कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार
- ✓ नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान एवं विनिर्माण पर अधिक फोकस

चुनौतियाँ (Concerns)
- ✗ निजी उपभोग में कमजोरी, विशेषकर ग्रामीण मांग में सुस्ती
- ✗ पूंजी-सघन क्षेत्रों से सीमित रोजगार सृजन – 'नौकरी रहित वृद्धि' का जोखिम
- ✗ उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल असमानता (Skill Mismatch)
- ✗ कर एवं GST संग्रह अपेक्षा से कम होने पर पूंजीगत व्यय पर दबाव
- ✗ बड़ी प्रौद्योगिकी योजनाओं का क्रियान्वयन जटिल और समय-साध्य

☆ **निष्कर्ष :** बजट 2026-27 सार्वजनिक निवेश, संरचनात्मक सुधारों, युवा सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर आधारित है। यह भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Union Budget 2026-27: Key Highlights

1. Theme

Vision: Viksit Bharat through Yuva Shakti (Youth Empowerment)

Three Pillars

1. Sustain Economic Growth
- Productivity
- Resilience
- Global Competitiveness

2. Fulfill Aspirations
- Capacity building
- Empowering youth through skills, education, innovation & opportunities

3. Sabka Saath, Sabka Vikas
- Inclusive and balanced development
- Last-mile delivery of benefits

Guiding Principles

- Action over Ambivalence
- Reform over Rhetoric
- People over Populism

2. Macroeconomic Outlook

Indicator	FY 2026-27 (BE)
Nominal Gross Domestic Product Growth	10%
Real Gross Domestic Product Growth	~7%
Fiscal Deficit	4.3% of Gross Domestic Product
Debt to Gross Domestic Product Ratio	55.6%
Capital Expenditure	₹12.21 lakh crore
Effective Capital Expenditure	₹17.1 lakh crore (4.4% of GDP)

- Total Expenditure : ₹53.47 lakh crore
- Revenue Expenditure : ₹41.25 lakh crore
- Net Tax Receipts : ₹28.67 lakh crore
- Disinvestment Target : ₹80,000 crore

3. Pillar I – Accelerate & Sustain Economic Growth

(A) Frontier Manufacturing

1. Biopharma SHAKTI
- Outlay: ₹10,000 crore over 5 years
- Focus on biologics & biosimilars
- 3 new National Institute of Pharmaceutical Education and Research
- Upgrade 7 existing National Institute of Pharmaceutical Education and Research
- Modernization of Central Drugs Standard Control Organization

2. India Semiconductor Mission 2.0
- Equipment manufacturing
- Raw material development
- Research and Development
- Industry-led skill development hubs

3. Electronics Components Scheme
- Outlay increased from ₹22,919 crore → ₹40,000 crore

4. Critical Minerals
- Establishment of Rare Earth Corridors in the states of:
  - Odisha
  - Kerala
  - Andhra Pradesh
  - Tamil Nadu
- Customs duty exemption on processing machinery

5. Chemical Parks
- 3 Plug-and-Play Chemical Parks to reduce import dependency

(B) MSME Push
- SME Growth Fund – ₹10,000 crore (to scale high-potential enterprises)
- Self-Reliant India Fund – ₹2,000 crore
- Scheme to upgrade 200 traditional industrial clusters with better infrastructure & technology
- Corporate Mitras – mentorship network to integrate micro and small firms into global value chains

(C) Infrastructure & Connectivity

1. Rail Connectivity
- 7 High-Speed Rail Corridors:
  - → Mumbai–Pune
  - → Pune–Hyderabad
  - → Hyderabad – Bengaluru
  - → Hyderabad – Chennai
  - → Chennai – Bengaluru
  - → Delhi – Varanasi
  - → Varanasi – Siliguri

2. Logistics & Waterways
- Dankuni – Surat Dedicated Freight Corridor
- Operationalization of 20 National Waterways
- Coastal Cargo Promotion Scheme to increase water transport share to 12% by 2047

3. Urban Development
- City Economic Regions (Cluster-based planning & mapping)
- ₹5,000 crore per region for 5 years through challenge mode

4. Risk Financing
- Infrastructure Risk Guarantee Fund to provide partial credit guarantees during construction phase & reduce project risks

4. Pillar II – Fulfill Aspirations

Creative & Orange Economy
- AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming and Comics) Content Creator Labs in 15,000 schools and 500 colleges through Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai

Women & STEM Inclusion
- Viability Gap Funding / capital support for constructing one girls' hostel in every district to promote education & participation

Tourism & Wellness
- Creation of 5 Regional Medical Hubs with integrated Allopathy, Agurveda and Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH) and diagnostics services
- Upgradation of National Council for Hotel Management and Catering Technology to National Institute of Hospitality

Sports Development
- Launch of comprehensive Khelo India Mission to identify, train and support sportspersons
- Dedicated Sports Goods Manufacturing Initiative to promote Make in India in sports equipment

5. Pillar III – Sabka Saath, Sabka Vikas (Inclusive & Balanced Development)

1. Agriculture – Bharat-VISTAAR
- Multilingual, Artificial Intelligence (AI)-driven advisory platform for farmers
- Integrates Agri Stack (digital public infrastructure) and Indian Council of Agricultural Research databases
- Provides localized crop, soil, water, weather, market and pest-management advice

2. Women Empowerment
- Launch of SHE Marts (Self-Help Entrepreneur Marts) within cluster federations
- To market products, provide branding, training, finance access & digital support
- Will strengthen Lakhpati Didi ecosystem and promote women-led enterprises

3. Health & Mental Well-being
- Establishment of NIMHANS-2 (National Institute of Mental Health and Neurosciences) for advanced mental health services
- Ranchi (Jharkhand) and Tezpur (Assam) institutes upgraded as Regional Apex Institutions for specialized care, research and training

4. Regional Development & Connectivity
- Development of Buddhist Tourism Circuit in the North-Eastern Region to promote spiritual tourism and local economies
- Durgapur Industrial Corridor – Node to strengthen manufacturing activities in West Bengal and Eastern India
- 4,000 Electric Buses for Eastern Region to improve public transport, reduce pollution and create green jobs

Impact of Pillar III
- Strengthens last-mile delivery of welfare schemes
- Reduces regional disparities
- Promotes sustainability, inclusion, gender equality and human development
- Uses technology and local strengths for balanced growth

6. Tax & Legislative Reforms

A. Direct Taxes & Legislative Changes

1. **New Income Tax Act, 2025**
   - Effective from 1 April 2026
   - Replaces Income Tax Act, 1961
   - Income tax slabs unchanged for FY 2026-27
2. **Share Buyback**
   - Tax burden shifted from company to shareholder
   - Buyback proceeds taxed as Capital Gains
3. **Securities Transaction Tax (STT) Increased**
   - Futures: 0.02% → 0.05%
   - Options: 0.10% → 0.15%
4. **Gift City (International Financial Services Centre)**
   - Tax holiday for Offshore Banking Units extended from 10 years to 20 years (taxed at 15% thereafter)
5. **Foreign Cloud Data Centres**
   - Tax holiday till 2047 for foreign entities providing cloud services through Indian data centres to overseas clients
6. **Compliance Reforms**
   - Decriminalisation of selected offences
   - (e.g., non-production of account books, non-payment of tax deducted at source in kind, etc.)
   - Immunity from prosecution for undisclosed foreign assets below ₹20 lakh (retrospective from 1 October 2024)

B. Indirect Taxes & Customs

1. **Tax Collected at Source (TCS) Rationalization**
   - TCS on foreign remittances under Liberalised Remittance Scheme (education/medical) and on overseas tour packages reduced to flat 2%
2. **Personal Import Duty**
   - General basic customs duty on personal imports reduced from 20% to 10%
3. **Duty Exemptions**
   - Full exemption on 17 cancer medicines
   - Full exemption on treatments for 7 rare diseases
4. **Export Support Measures**
   - Increase in duty-free input import limits for Marine, Leather and Textile sectors to enhance global competitiveness

7. Analytical Assessment

Positive Outlook
- ✓ Record public capital expenditure – crowding in private investment
- ✓ Continued fiscal consolidation – deficit at 4.3% of GDP
- ✓ Strategic focus on high-tech manufacturing (semiconductors, biopharma, electronics & rare earths)
- ✓ Strong push for MSMEs and traditional industry clusters
- ✓ Major boost to logistics, rail, waterways and urban decentralisation
- ✓ Emphasis on innovation, AI, digital agriculture and human capacity building for long-term growth

Concerns / Challenges
- × Weak private consumption and sluggish rural demand may limit overall growth
- × Capital-intensive sectors may lead to 'jobless growth' if reskilling is not accelerated
- × Skill mismatch in advanced technology sectors
- × Revenue buoyancy risks could constrain fiscal space
- × Execution bottlenecks and regulatory delays in large technology and infrastructure missions